



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 भाद्र 1939 (श10)
(सं0 पटना 864) पटना, बुधवार, 20 सितम्बर 2017

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

13 सितम्बर 2017

सं0सं0 ग्रा0वि0-14(विविध)न्याय-07/2015-327923—माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0 सी0 संख्या- 19529/2011 सदानंद यादव बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य तथा अन्य बैच वादों में दिनांक 21.09.2015 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु राज्य सरकार के द्वारा जाँच अधिनियम 1952 (सं0-60, 1952) की धारा 3(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में वर्ष 2002 से 2006 की अवधि में कार्यान्वित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के समापन के उपरान्त अवशेष खाद्यान्न की क्षति के लिए उत्तरदायित्व के निर्धारण एवं उसके समतुल्य राशि की वसूली हेतु एक त्रिसदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग का गठन अधिसूचना सं0- 258459 दिनांक 18 जनवरी 2016 द्वारा किया गया। इस जाँच आयोग के कार्यकाल को छः माह की स्वीकृति पूर्व में सरकार के द्वारा दी गयी थी एवं अधिसूचना सं0-278503 दिनांक 18.07.2016 एवं अधिसूचना सं0- 298341 दिनांक 27.01.2017 द्वारा इसके कार्यकाल को छः-छः महीने के लिए बढ़ाया गया था, जो कि दिनांक 17.07.2017 को समाप्त हो गया है।

आई0ए0 सं0-5268/2017 के संदर्भ में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या- 5638/2011 में दिनांक 02.08.2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं आयोग के अनुरोध पर बिहार के राज्यपाल आयोग को न्यायमूर्ति श्री उदय सिन्हा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग बनाने के साथ-साथ इसके कार्यकाल को अगले छः माह यथा 18.07.2017 से 17.01.2018 तक विस्तारित करते हैं।

2. आयोग के विचारणीय बिन्दु जो अधिसूचना संख्या 258459 दिनांक 18.01.2016 के द्वारा निर्धारित है, को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है:-

- (क) आयोग केवल उन व्यक्तियों के परिवारों पर सुनवाई करेगा जिनकी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० सख्या- 19529/2011 के साथ दिनांक 21.09.2015 को आदेश पारित किया था।
- (ख) वैसे व्यक्ति या जनवितरण प्रणाली के विक्रेता जो उपरोक्त वाद में वादी नहीं हैं, और जिन्होंने याचिका में अपनी माँगों को नहीं रखा है, उन्हें अपनी माता आयोग के समक्ष रखने की अनुमति नहीं होगी।
- (ग) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वैसे जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं की सुनवाई आयोग के समक्ष हो पाएगी जिनके द्वारा उपस्थिति के पूर्व निलाम पत्र में सन्निहित राशि का 50 प्रतिशत जमा कर दिया गया हो।
3. दिनांक 17.01.2018 तक आयोग अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

संजय कुमार सिंह,

सरकार के सश्रुक्त सचिव।

The 13th September 2017

No. स०स० ग्रा०वि०-14(विविध)न्याय-07/2015-327923— In compliance of the order passed by the Hon'ble Patna High Court on 21.09.2015 in the CWJC No. 19529/2011 Sadanand Yadav & Others Versus State of Bihar and Others and other batch cases, Government of Bihar vide notification no.- 258459 dated 18th January, 2016 decided to appoint a three member Judicial Commission of Enquiry for fixing the responsibility for the loss of residual food grain after the closing of Sampurn Gramin Rojgar Yojana and National Food for Work Scheme between 2002 to 2006, in exercise of powers conferred under Section 3(1) of the Commission of the Enquiry Act 1952 (No. 60, 1952). The government initially approved the tenure of the Commission for six months and extended its tenure for another six months twice vide notification no. 278530 dated 18th July 2016 and 298341 dated 27.01.2017, which expired on 17.07.2017.

The order passed by the Hon'ble Patna High Court on 02.08.2017 in C.W.J.C. No.- 5638/2011 in reference to Interlocutory Application No. 5268 of 2017 and on the request of Commission the Governor of Bihar is pleased to make it one member Commission headed by Justice Uday Sinha (Rtd.) and extend the tenure for another six month from 18.07.2017 to 17.01.2018.

(2) The terms of reference of the Commission as notified vide notification no. 258459 dated 18.01.2016 shall be modified as follows—

- The Commission shall cause an enquiry only with regard to the grievances of such of the persons who had filed the Writ Petition before the Honourable High Court pertaining to which orders were passed on 21.09.2015 in C.W.J.C. No.- 19529/2011 and analogous cases.
 - The persons or PDS dealers who are not parties in the Writ Petitions or who had not ventilated their grievances in the Writ Petitions shall not be permitted to take up the issue before the Commission.
 - As per order of Hon'ble High court only such PDS dealer shall be heard by the Commission who deposit 50% of certificate amount before appearance,
- (3) The Commission shall submit its report before 17.01.2018.

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR SINGH,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 864-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>